प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

हमारा घोषणा पत्र जनता की तरफ से आएगा, जो वास्तव में इस देश के प्रभारी हैं ...
- जॉन बोएनर

अमेरिकी राजनेता

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की है, जिससे आवास, वाहन और निजी ऋणों की किस्तें कम हो सकती हैं, अहम यह है कि यदि महंगाई नियंत्रित रही, तो कटौती का यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है।

एक और राहत

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस वित्त वर्ष की अपनी पहली द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की जो कटौती की है, वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के नियंत्रित रहने और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती की वजह से अपेक्षित ही थी। सात फरवरी को हुई अपनी पिछली बैठक में भी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी और मौद्रिक नीति समिति के 2016 में गठित होने के बाद यह पहला मौका है, जब रेपो रेट में लगातार दो बार कटौती की गई है। दो बार की कटौती से रेपो रेट छह फीसदी रह गया है, जिससे बैंकों के पास कर्जदाताओं को राहत देने की गुंजाइश काफी बढ़ गई है। चुनावी मौसम में इस कटौती से आम उपभोक्ताओं को आवास, वाहन और निजी ऋणों की मासिक किस्तों में रियायत मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि महज दो महीने के दौरान रिजर्व बैंक से 50 बेसिस पॉइंट में कटौती के रूप में मिली रियायत का कितना हिस्सा बैंक अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। मगर जितनी भी रियायत मिलेगी, उससे उपभोक्ताओं के पास खर्च करने लायक पैसा बढ़ेगा, जिससे बाजार में गतिविधियां तो तेज होंगी ही, नए निवेशक भी प्रेरित होंगे। अहम यह है कि महंगाई की दर रिजर्व बैंक के चार फीसदी से अधिक न होने के लक्ष्य पर नियंत्रित है और यदि आगे भी महंगाई नियंत्रित रही, तो कटौती का यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि यह सब वैश्विक परिदृश्य पर निर्भर करेगा, क्योंकि पिछली कटौती के बाद कच्चे तेल के दाम दस फीसदी बढ़ चुके हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनवरी और फरवरी में निर्यात और विशेष रूप से गैर तेल और गैर स्वर्ण क्षेत्र का आयात भी घटा है; तो यह कमजोर औद्योगिक मांग को ही बताता है। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने फरवरी में हुई अपनी बैठक में 2019-20 में विकास दर के 7.4 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया था, लेकिन अब उसका अनुमान है कि इसमें कमी होगी और यह 7.2 फीसदी हो सकती है। जाहिर है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की अगली बैठक जब जून में होगी, तब तक चुनाव निपट चुके होंगे, लेकिन जो भी नई सरकार बनेगी, उसे इन चुनौतियों से निपटना होगा।

बीच बहस में घोषणापत्र

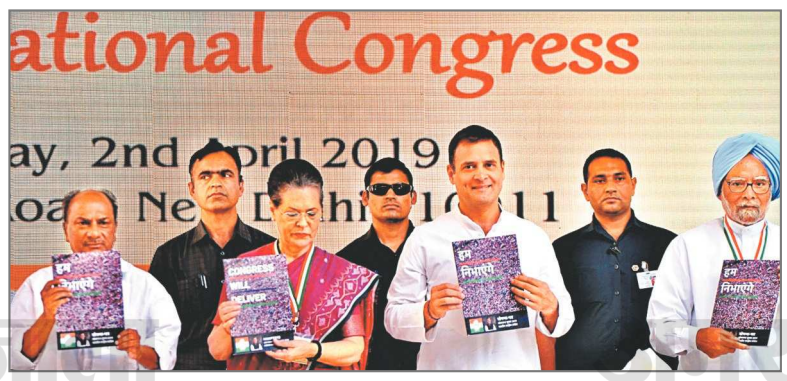

एक समय था, जब चुनावी घोषणापत्रों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन हाल में जारी कांग्रेस का घोषणापत्र अच्छी तरह से तैयार दस्तावेज है, जिसमें चुनाव को आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश की गई है।

नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार

दिवंगत जाट नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र का तिरस्कार करते थे। वह कहते थे कि सभी पार्टियों के घोषणापत्रों में कमोबेश एक जैसी ही सामग्री होती है, इसलिए आप अंदर की सामग्री उठाकर उसके आवरण पर अपना नाम और अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न डालकर काम चला सकते हैं।

एक समय था, जब चुनावों में घोषणापत्रों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। घोषणापत्र प्रेस को जारी किए जाते थे और फिर वे पार्टी कार्यालय में ढेर के रूप में पड़े रहते थे, जिन्हें बाद में रद्दी के रूप में बेच दिया जाता था। मीडिया भी उसमें मात्र कुछ घंटे ही दिलचस्पी दिखाता था। वे औपचारिकता निभाने के लिए उसके बारे में लिखते थे और फिर किसी को याद नहीं रहता था कि उसमें क्या कहा गया है। राजनेता स्वयं भी उसे एक रस्म के तौर पर जारी करते थे, जो उन्हें करना होता था और फिर तुरंत उसे भुला देते थे।

लेकिन चीजें बदल रही हैं और अन्यथा तेजी से विवादास्पद होती राजनीति में यह एक सकारात्मक पहलू है। घोषणापत्र आखिर मतदाताओं को विकल्पों के बारे में सूचित करने में मददगार ही होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति आखिरकार पार्टियों को उनके वादे के हर पहलू पर अधिक सोचने के लिए मजबूर कर रही है, जिसमें योजनाओं का वित्तपोषण भी शामिल है और क्रियान्वयन भी। आप मानें या न मानें, पर हाल में जारी कांग्रेस का घोषणापत्र अच्छी तरह से तैयार दस्तावेज है, और अगर राहुल गांधी की मानें, तो इसे तैयार करने में छह महीने लगे हैं। पार्टी ने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से सलाह करके न्याय योजना तैयार की है, जिसके तहत बीस फीसदी अति निर्धन परिवारों को प्रति महीने 6,000 रुपये देने का वादा किया गया है।

खैरात बनाम विकास पर बहस को अलग रखें, तो न्याय योजना ने सत्तारूढ़ पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। रोजगार का अभाव आज अन्य किसी भी मुद्दे की तुलना में लोगों को ज्यादा आंदोलित कर रहा है, भले ही इसे पुलवामा और बालाकोट मामले से ढकने की कोशिश हो रही हो। भाजपा समर्थकों तक का मानना है कि इसका असर हो सकता है। सवाल हालांकि यह है कि क्या कांग्रेस आखिरी मतदाता तक अपना संदेश पहुंचा पाएगी। जैसे कांग्रेस बार-बार प्रत्येक व्यक्ति के खाते में पंद्रह लाख रुपये ट्रांसफर करने और दो करोड़ रोजगार सृजित करने के वादे पूरे न कर पाने के लिए भाजपा की खिंचाई करती है, वैसे ही भाजपा 50 साल से अधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस की गरीबी उन्मूलन में विफल रहने के लिए आलोचना कर रही है, जिसका वह अभी वादा कर रही है। वे कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ही 1971 के चुनाव में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था।

कांग्रेस ने जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का वादा किया है, जो सबसे आकर्षक है। हमारे सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को देखते हुए कांग्रेस ने बारहवीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी वादा किया है। स्वाभाविक रूप से भाजपा प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, बुनियादी संरचनाओं का निर्माण और शिक्षकों को प्रशिक्षित कौन करेगा।

अपने बच्चों को स्वास्थ्य-पोषण और शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार दिए बिना भारत नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। हम सभी जानते हैं कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो रास्ते निकल आते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिस्पर्धी राजनीति भाजपा को कांग्रेस के इस दांव का काट ढूंढने के लिए विवश करती है या नहीं और मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सामने इसका कोई रास्ता है या नहीं।

अलबत्ता यह हैरान करने वाला है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में बाल कुपोषण से मुकाबला करने के लिए ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जबकि हार्वर्ड के एक प्रोफेसर के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, सोनिया गांधी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य प्रमुख नेताओं के संसदीय क्षेत्र में बौनेपन और एनीमिया की स्थिति भीषण है। घोषणापत्र में हालांकि बच्चों के लिए पोषक आहार की गुणवत्ता में सुधार के लिए समेकित बाल विकास योजना के विस्तार के बारे में जोर डाला गया है। पर इसमें कुपोषण खत्म करने के लिए देशव्यापी युद्ध छेड़ने की बात शामिल नहीं है। यह तब है, जब देश के हर पांच में से दो बच्चे बौने कद के हैं और खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कुपोषण को 'राष्ट्रीय शर्म' बता चुके हैं।

घोषणापत्र के जरिये कांग्रेस ने चुनावी बहस को आर्थिक मुद्दों पर लाने की कोशिश की है, जिसने इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बढ़त प्रदान की। उसने न सिर्फ न्याय का वादा किया है, बल्कि मनरेगा में भी कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 करने, 22 लाख खाली सरकारी पदों को भरने और ग्राम पंचायतों में दस लाख रोजगार पैदा करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा संकटग्रस्त किसानों के लिए भी संदेश है, जैसे पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों के लिए अलग बजट, या कर्ज न चुकाने वाले किसानों पर आपराधिक नहीं, बल्कि दीवानी मुकदमा चलाने जैसी बात, आदि।

लेकिन भाजपा को राष्ट्रवाद के अपने प्रमुख मुद्दे पर वापस लौटने में मिनट भी नहीं लगे। अरुण जेटली ने राजद्रोह कानून खत्म करने तथा अफ्स्पा पर पुनर्विचार करने जैसे वादों को 'खतरनाक' बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने पिछले रिकॉर्ड के विपरीत मानवाधिकार का सम्मान करते हुए उदार बातें करने की कोशिश कर रही है, जिनका कुछ लोगों द्वारा स्वागत किया जा सकता है।

घोषणापत्र के वादों पर जंग ने एक बार फिर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और 2019 के चुनावी समर का मुख्य विषय है-राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम रोजगारहीनता। इसने यह भी रेखांकित किया है कि मतदाताओं से ज्यादा विरोधी पार्टी ही अपने प्रतिद्वंद्वी के वादों पर नजर रखेगी और उसे पूरा किए जाने पर सतर्क रहेगी। उम्मीद है, इससे दोनों पक्षों में जवाबदेही बढ़ेगी। लेकिन यह हमारी राष्ट्रीय बहस से बीच की जगह के गायब होते जाने के प्रति चेतावनी भी है।

अंतर्ध्वनि

>> विद्यानिवास मिश्र

जिनके साथ रहें, उनमें मौज भर देने की क्षमता रखें

मैं बहुत ही एकाकी व्यक्ति हूं। मैं जितना ही जनसमुदाय के साथ मिलता-जुलता हूं, उतना ही और अपने को विजन एकांत में पाता रहता हूं। कारण यह है कि जीवन के सभी रसों में रमने की चाह है, पर कहीं भी विलमने की धीरता नहीं है और साथ ही किसी से बिछुड़ने की निठुरता भी नहीं है। चाहता हूं, किसी से प्रीति न करूं पर प्रीति हो जाती है, तो उसे छोड़ने की बात भी सोच नहीं पाता। 'उड़ी न सकत उड़िबे अकुलाते' वाली स्थिति सदा बनी रहती है। एक चिरंतन आकुलता ही मेरे जीवन का पर्याय बन गई है। इसलिए जब कोई तीखी बात हो जाती है, तो मन में सहज ही विरसता फैलने लगती है, पर ज्योंही उसमें कुछ तितास आने लगती है, त्योंही सोचता हूं कि दुखों को हंसकर झेलनेवाले मेरे किसी पूर्व साथी ने यह सिद्धांत स्थापित किया था, 'थोड़ा कमाएं, उससे थोड़ा ही कम खर्च करें, थोड़े से मित्र रखें पर बिना किसी प्रतिदान की शर्त बदें, थोड़े से लोगों में रमें-घूमें और थोड़े समय भी जिनके साथ रहें, उनमें और मौज भर देने की क्षमता रखें। उन थोड़े से लोगों को भी तजने की क्षमता हो, पर बिना मन में तितास लिए हुए; क्या इससे अधिक भी चाहने की मानव जीवन में आवश्यकता है?' वह व्यक्ति मेरा जीवन-गुरु नहीं, मेरे पथ का पूर्वयात्री राबर्ट लुई स्टीवेंसन है, जिसने मुझे अक्षर डगर दिखाई है। और तब सोचता हूं कि मुझे रोग में घुलना बदा ही हो, पर नीम का काढ़ा मुझे नसीब न हो। आज के कड़वेपन के साथ मेरा जो घोर अंतर्विरोध है, उसकी उपशांति भी मुझे इस काषाय में मिलती है। इसकी यही विशेषता है कि वह तिक्तता का परिशोध तो करती ही है, साथ ही ऐसी स्वादभूमि तैयार करती है कि उसके बाद अस्वादु चीज भी मधुर प्रतीत हो।

-दिवंगत हिंदी साहित्यकार

मंजिलें और भी हैं

>> डॉ. हरशिंदर कौर

कन्या भ्रूणहत्या की एक घटना ने मुझे बदल दिया

मैं एक डॉक्टर हूं। करीब पच्चीस साल पहले एक दिन मैं अपने पति के साथ, जो खुद भी डॉक्टर हैं, पंजाब-हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों से गुजर रही थी। वह पूरा इलाका भीषण गरीबी से ग्रस्त लगता था। हम असल में उसी इलाके के एक गांव में लगे चिकित्सा कैंप में काम करने के लिए जा रहे थे। वह थोड़ी ही दूर रह गया था कि एक जगह हमें एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। वह सामान्य आवाज नहीं थी, इसलिए मेरे पति ने उसी दिशा में अपनी गाड़ी मोड़ ली। आगे श्मशान जैसी जगह थी, जहां जगह-जगह जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। उसी से थोड़ा आगे कुछ कुत्ते वहीं पड़े एक नवजात शिशु का हाथ नोच रहे थे। रुदन उसी नवजात शिशु का था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब तक हम वहां पहुंचते, कुत्तों ने उस नवजात बच्ची की जान ले ली थी। हम उस गांव में गए और घर-घर जाकर लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछताछ की। ज्यादातर लोगों ने उस घटना के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। एक आदमी ने हमें जो कहा, वह हैरान करने वाला था। उसका कहना था कि हो सकता है कि वह बच्ची किसी गरीब की हो, जो उसे पालना न चाहता हो।

मैंने दहेज के खिलाफ भी मुहिम चलाई है, क्योंकि यह भी एक सामाजिक बुराई है।

अब तक हम पति-पत्नी पंजाब के दूरस्थ इलाकों में मेडिकल कैंप लगाते और गरीबों का इलाज करते थे। लेकिन इस घटना ने मुझे हिला दिया था। मैंने कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ काम करने और लोगों को बच्चियों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने का फैसला किया। हालांकि पीसीपीएनडीटी कानून 1994 में अमल में आ चुका था, इसके बावजूद पंजाब और हरियाणा में हर साल कन्या भ्रूणहत्या के हजारों मामले सामने आ रहे थे। 1996 से 1998 के बीच पंजाब में 51,000 और हरियाणा में 62,000 गर्भपात के मामले सामने आए थे। कानून होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड के जरिये गर्भ में पल रहे बच्चे की लैंगिक जानकारी हासिल करने और फिर गर्भपात कराने का चलन पूरे देश में है।

बहुत खोजबीन के बाद मैंने पटियाले के पास का एक गांव चुना और वहां मैं पांच साल रही। शुरू-शुरू में लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं बच्चियों के मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सुख-सुविधाएं छोड़कर गांव में रहने आई हूं, तो वे मुझसे प्रभावित हुए। मैं उस गांव के हर घर में गई और मर्दों से बैठकर मैंने बातें कीं। मैंने उनसे यह भी कहा कि यह सामाजिक जागरूकता आप अपने परिचितों में भी फैलाइए, ताकि समाज बदले। पांच साल बाद जब मैं उस गांव से निकल रही थी, तब वहां बच्चियों की संख्या बच्चों से अधिक हो चुकी थी।

कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ लड़ाई में मुझे सामाजिक विरोध का ही सामना नहीं करना पड़ा, मेरे अनेक वरिष्ठों ने भी समय-समय पर मुझसे असहमति जताई। एक बार एक वैश्विक सम्मेलन में मैंने अपने यहां के ग्रामीण इलाकों की भयावह सच्चाई के बारे में बताया, तो दंड स्वरूप कई दिनों तक अस्पताल में मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैंने दहेज के खिलाफ भी मुहिम चलाई है, क्योंकि यह भी एक सामाजिक बुराई है। वर्ष 2008 में मैंने पति और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर डॉ. हर्ष चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की संस्था गठित की, जिसके तहत पंजाब के गरीब घरों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मेरी मुहिम हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन समाज में बच्चियों के प्रति आई जागरूकता से मैं संतुष्ट हूं।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

बाजार के रास्ते चीन की घेराबंदी

भारत के पास मजबूत उपभोक्ता बाजार है और यह बाजार चीनी कंपनियों की बड़ी जरूरत है। ऐसे में यदि भारत के उपभोक्ता बाजार में स्वदेशी भावना से चीनी सामान पर कुछ नियंत्रण लग जाए, तो यह चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा।

जयंतीलाल भंडारी

भारत चीन की आर्थिक चुनौती को स्वीकार करने को तैयार दिख रहा है। हाल ही में भारत ने चीन की 'बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) को लेकर होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है। चीन ने 2017 में बीआरआई की पहली बैठक आयोजित की थी और भारत ने उसका भी बहिष्कार किया था। बीआरआई के तहत छह गलियारे बनाने की योजना है, जिनमें से कई गलियारों पर काम भी जारी है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है। भारत चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में भारत की इजाजत के बिना चीन वहां से आर्थिक गलियारा नहीं बना सकता है।

गौरतलब है कि चीन की बीआरआई परियोजना का अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने भी विरोध किया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन की यह परियोजना जिन देशों से गुजरेगी, उन देशों के किए यह आर्थिक सहयोग कम और खतरा ज्यादा उत्पन्न करेगी। बीआरआई परियोजना का मकसद दुनिया भर में चीन के निवेश से बुनियादी परियोजनाओं का विकास करना और चीन के प्रभुत्व को बढ़ाना है। चीन ने आर्थिक मंदी से उबरने, बेरोजगारी से निपटने और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 2013 में यह परियोजना पेश की।

इसके तहत चीन ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क मार्ग, रेलमार्ग, गैस पाइप लाइन और बंदरगाह से जोड़ने के लिए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मेरीटाइम सिल्क रोड परियोजना शुरू की है। ऐसे में दुनिया के अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि बीआरआई परियोजना को लेकर होने वाली बैठक के बहिष्कार और अमेरिका तथा जापान के साथ वैश्विक मंच पर चीन की इस परियोजना का विरोध करके भारत ने चीन से आर्थिक मुकाबले की शुरुआत कर दी है।

पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और मसूद अजहर के मामले में चीन के अड़ियल रवैये को भारत ने चुनौती की तरह स्वीकार किया है। चीन के खिलाफ दोहरी रणनीति की जरूरत है। एक तो सरकार के स्तर पर आर्थिक रणनीति बनाई जाए और दूसरा है, करोड़ों उपभोक्ताओं द्वारा चीनी वस्तुओं का विरोध। बेशक चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले पांच गुना बड़ी है और वह सैन्य ताकत के मामले में भी आगे है। इसके बावजूद भारत के पास 110 लाख करोड़ रुपये का मजबूत उपभोक्ता बाजार है और यह बाजार चीनी कंपनियों की बड़ी जरूरत है। ऐसे में यदि भारत के उपभोक्ता बाजार में स्वदेशी भावना से चीनी सामान पर कुछ नियंत्रण लग जाए, तो यह चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। भारत में सस्ते चीनी सामान की आवक तेजी से बढ़ी है। भारत के कई उद्योग भी कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। देश के कोने-कोने के बाजारों में चीन में उत्पादित वस्तुओं का ढेर लग गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीन के मोबाइल भारत में बिकते हैं। चूंकि चीन में जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2018 में घटकर 6.6 फीसदी पर आ गई है। यह दर 1990 से यानी पिछले 28 वर्षों में अब तक की सबसे धीमी जीडीपी वृद्धि दर है। ऐसे में धीमी पड़ती हुई चीनी अर्थव्यवस्था पर भारतीय बाजार से मांग कम होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चीन अपनी आर्थिक मंदी को कम करने के लिए बीआरआई परियोजना पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में चीन के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने की रणनीति को आगे बढ़ाना होगा।

खुली खिड़की

मधुमेह का मीठा जहर

जीवन-शैली का भी स्वास्थ्य पर खासा प्रभाव पड़ता है। मधुमेह (डायबिटीज) भी एक ऐसी ही बीमारी है, जिससे सर्वाधिक प्रभावित चीन के लोग हैं, जबकि दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका है।

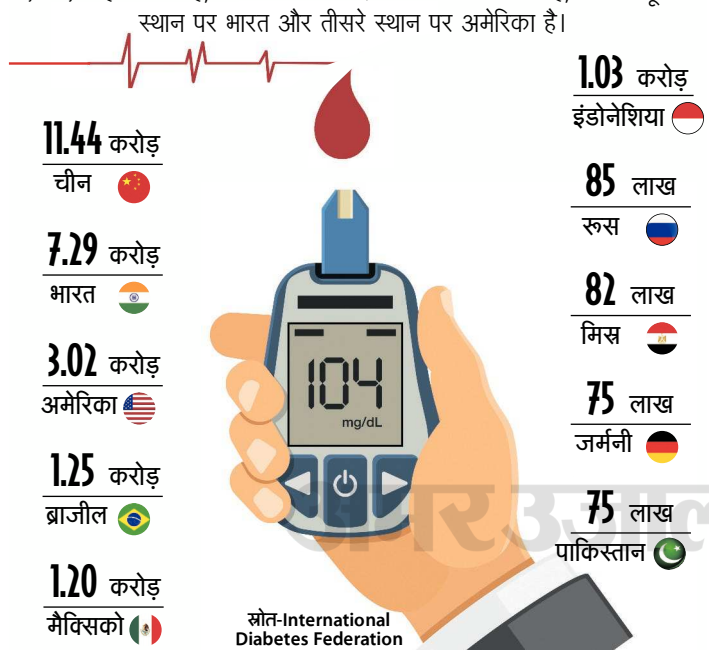

सत्संग

धर्म और भ्रम

चीन में एक समय महान दार्शनिक ताओ बू हुए। उनकी विद्वता की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए पहुंचते। चुंगसिन ने भी ताओ बू की ख्याति के बारे में सुन रखा था। वह ताओ बू का शिष्य बनकर उनसे धर्म की शिक्षा लेना चाहता था। एक दिन वह घर छोड़कर ताओ बू से मिलने निकल पड़ा। वह आबादी से बाहर दुर्गम इलाके में घने जंगल में रहते थे। चुंगसिन ने उनका अभिवादन करने के बाद जब अपने आने का उद्देश्य बताया, तो ताओ बू ने कुछ खास नहीं कहा। आश्रम में ताओ बू के और भी कुछ शिष्य रहते थे। चुंगसिन भी वहीं रहने लगा। धीरे-धीरे उसने आश्रम का कायदा-कानून समझ लिया। आश्रम में अलग से कोई कायदा-कानून था भी नहीं। यहां तक कि ताओ बू को उसने पढ़ाते या शिक्षा देते भी कभी नहीं देखा। आश्रम में रहते हुए चुंगसिन को एक साल हो गया। लेकिन ताओ बू ने उसे कभी एक भी पाठ नहीं पढ़ाया था। चुंगसिन अब थोड़ा हताश था और नाराज भी। उसने आश्रम छोड़ देने के बारे में सोचा। वह ताओ बू से मिलने गया, तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, जा रहे हो? नाराज चुंगसिन ने कहा, क्यों न जाऊं! आपने कुछ सिखाया ही नहीं। ताओ बू बोले, धर्म तो जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जबकि तुम धर्म को दैनिक जीवन से अलग समझते हो। यही तुम्हारा भ्रम है, चुंगसिन। चुंगसिन गुरु के कहे का अर्थ समझ गया।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

किशोर, मैनेजर और सेब

किशोर की कहानी, जिसे ऑफिस बॉय की नौकरी नहीं मिली, तो मेहनत करके वह बड़ा व्यवसायी बन गया।

मैनेजर ने किशोर से पूछा, क्या तुम कंप्यूटर चलाना जानते हो? किशोर बोला, सर, जानता तो नहीं, पर सीख लूंगा। मैनेजर ने पूछा, क्या तुम्हारा ई-मेल आईडी है? किशोर बोला, जी नहीं, पर कंप्यूटर सीखकर ई-मेल आईडी भी बना लूंगा। मैनेजर बोला, हमारे पास इतना समय नहीं। किशोर मायूस होकर वहां से निकल गया। वह बारहवीं पास कर चुका था। पर पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। एक ऑफिस बॉय की नौकरी का उसे पता चला, इसीलिए आया था। वहां से निकलकर वह पास के सेब के एक बगीचे में जाकर बैठ गया। वह बेहद हताश था। तभी उसकी नजर सेबों पर पड़ी। उसने बगीचे से कुछ सेब तोड़े, और उन्हें घर-घर जाकर बेचने लगा। सेब ताजा थे, इसलिए बिक भी गए। सेब बेचकर उसे लगभग सौ रुपये मिले। उन पैसों से वह दोबारा बाजार से सेब खरीद लाया। सौ रुपये के सेब उसने डेढ़ सौ रुपये में बेचे। शाम तक उसने करीब तीन सौ रुपये कमा लिए। अगले दिन सौ रुपये के सेब से शाम तक उसने करीब छह सौ रुपये कमा लिए। इस तरह उसने सेब का ठेला, फिर दुकान, फिर कई दुकानें खरीद लीं। उसके अपने सेब के बगीचे हो गए और वह एक बड़ा व्यवसायी बन गया। लगभग दस साल बीत गए। एक दिन वह उसी बगीचे के पास से गुजर रहा था। उसने गाड़ी रुकवाई। बड़ी गाड़ी देख बगीचे का मालिक वहां पहुंच गया। उसे लगा, शायद किशोर उसका बगीचा खरीदने आया है। किशोर बोला, मैं आज जो कुछ हूं, आपकी वजह से हूं। बगीचे का मालिक हैरान हो गया। फिर किशोर ने अपनी कहानी उन्हें सुनाई। बगीचे का मालिक बोला, आपने कभी सोचा है कि यदि कंप्यूटर चलाना आता होता, तो आप आज कहां होते? किशोर बोला, तो शायद मैं आज भी एक ऑफिस बॉय ही होता।

अगर जज्बा हो, तो शून्य से शुरू कर भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है।